



Daily

करेंट

अफेयर्स

» 12 जून 2025

NATIONAL AFFAIRS / GOVERNMENT SCHEME

1. प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 9 वर्ष पूरे हो गए और मातृ जोखिम न्यूनीकरण (MRR) में 50 अंकों की गिरावट आई।



जून 2025 में, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW), भारत सरकार (GoI) की एक प्रमुख पहल, अपनी 9वीं वर्षगांठ मनाएगी।

- PMSMA का उद्देश्य उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं का शीघ्र पता लगाने और समय पर प्रबंधन करके मातृ एवं नवजात मृत्यु दर को कम करना है।

- मई 2025 तक, देश भर में PMSMA के तहत 6.19 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं को प्रसवपूर्व जांच का लाभ मिला है।

- भारत के मातृ मृत्यु अनुपात (MMR) में 50 अंकों की उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है - जो 2014-2016 के दौरान प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर 130 से घटकर 2021-2023 के दौरान प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर 80 हो गई है - जो मातृ स्वास्थ्य देखभाल परिणामों में उल्लेखनीय सुधार को दर्शाता है।

Key Points:-

(i) जून 2016 में शुरू की गई PMSMA की शुरुआत सभी गर्भवती महिलाओं को हर महीने की 9 तारीख को, विशेष रूप से दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान, निःशुल्क सुनिश्चित, व्यापक और गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व देखभाल (ANC) सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई थी।

(ii) यह पहल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल और किशोर स्वास्थ्य प्लस पोषण (RMNCAH+N) रणनीति के व्यापक लक्ष्यों के अनुरूप है।

(iii) यह अभियान निजी क्षेत्र के सहयोग के एक व्यवस्थित मॉडल का अनुसरण करता है, जिसमें निजी चिकित्सकों को स्वेच्छा से कार्य करने, जागरूकता प्रयासों में योगदान देने तथा अभियान के तहत सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में सेवाएं प्रदान करने में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

2. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र के पुणे में 'स्वच्छ पौधा कार्यक्रम' का शुभारंभ किया।



केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र के पुणे में 01 जून से 03 जून, 2025 तक आयोजित भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकथॉन के समापन सत्र के दौरान भारत भर में 9 बागवानी सुविधाएं स्थापित करने के लिए 'स्वच्छ पौधा कार्यक्रम' शुरू करने की घोषणा की।

- इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर में बागवानी विकास को बढ़ावा देने और किसानों की उत्पादकता में सुधार लाने के लिए रोग-मुक्त और उच्च गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री की उपलब्धता को बढ़ाना है।

- बागवानी अनुसंधान और विकास को बढ़ाने पर भारत के फोकस ने नौ केंद्रीय रोपण फसलों (CPC) की पहचान की है, जिनकी खेती और अनुसंधान विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। इनमें शामिल हैं: अंगूर (राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, पुणे, महाराष्ट्र); शीतोष्ण फल जैसे सेब, बादाम और अखरोट (केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर और मुक्तेश्वर, उत्तराखंड); खट्टे फल जैसे संतरे (ICAR-केंद्रीय खट्टे फल अनुसंधान संस्थान, नागपुर, महाराष्ट्र और ICAR-केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर, राजस्थान); आम, अमरूद और एवोकाडो (ICAR-भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलुरु, कर्नाटक); आम, अमरूद और लीची (ICAR-केंद्रीय उपोष्णकटिबंधीय बागवानी संस्थान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश); और अनार (राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, शोलापुर, महाराष्ट्र)। पूर्वी भारत में उपोष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय फलों के लिए सुविधाओं का विकास भी होगा।

- कुल नौ सी.पी.सी.-विशिष्ट सुविधाओं में से तीन महाराष्ट्र में स्थापित की जाएंगी। ये पुणे (अंगूर के लिए), नागपुर (संतरे के लिए) और सोलापुर (अनार के लिए) में स्थित हैं। महाराष्ट्र

स्थित इन तीन बागवानी अनुसंधान केंद्रों की संयुक्त विकास लागत ₹300 करोड़ होने का अनुमान है।

Key Points:-

(i) स्वच्छ संयंत्र पहल को इजरायल और नीदरलैंड सहित अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों से विशेषज्ञ तकनीकी सहायता प्राप्त होगी।

(ii) यह पहल उन्नत नर्सरियों के विकास को भी बढ़ावा देगी, जिसमें बड़ी नर्सरियों के लिए 3 करोड़ रुपये और मध्यम आकार की नर्सरियों के लिए 1.5 करोड़ रुपये का वित्त पोषण किया जाएगा।

(iii) कार्यक्रम के दौरान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस ने घोषणा की कि राज्य सरकार प्रतिभागियों के विचारों को स्केलेबल स्टार्टअप में बदलने के लिए इनक्यूबेशन और वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु भारत सरकार (जीओआई) के समर्थन के साथ-साथ अपने 120 करोड़ रुपये के स्टार्टअप फंड ऑफ फंड्स (एफओएफ) का उपयोग करेगी।

3. बंगलुरु को भारत की 'तेंदुए राजधानी' घोषित किया गया, जहां 85 जंगली तेंदुए खुलेआम घूम रहे हैं।



जून 2025 में, बेंगलुरु (कर्नाटक) को भारत की 'तेंदुए की राजधानी' घोषित किया गया, जिसके बाद होलेमाथी नेचर फाउंडेशन (HNF) द्वारा एक साल तक कैमरा-ट्रैप सर्वेक्षण (2024-2025) किया गया, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। प्रसिद्ध संरक्षण जीवविज्ञानी डॉ. संजय गुब्बी के नेतृत्व में किए गए सर्वेक्षण से पता चला कि बेंगलुरु में भारत के महानगरों में सबसे ज्यादा जंगली तेंदुओं की आबादी है, जो मुंबई (महाराष्ट्र) से भी ज्यादा है।

- अध्ययन में अनुमान लगाया गया कि बेंगलुरु के आसपास के जंगलों और झाड़ियों में 80-85 तेंदुए हैं, जो महाराष्ट्र के संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में दर्ज मुंबई के 54 तेंदुओं से अधिक हैं।

- सर्वेक्षण में 250 से अधिक कैमरा ट्रैप का उपयोग करके 282 वर्ग किलोमीटर (वर्ग किमी) के क्षेत्र को कवर किया गया, जिसमें तुराहल्ली, बी.एम. कावल, यू.एम. कावल, रोरिक एस्टेट और बन्नरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान (BNP) सहित मिश्रित आवासों से डेटा एकत्र किया गया।

- कुल तेंदुओं में से 54 बन्नरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान (BNP) के अंदर दर्ज किए गए, जबकि 30 से अधिक तेंदुए शहर के बाहरी इलाकों में आरक्षित, मान्य और निजी वन भूमि में पाए गए।

Key Points:-

(i) इसके साथ ही, बेंगलुरु ने 'भारत की तेंदुआ राजधानी' का खिताब अर्जित कर लिया, और यह एकमात्र भारतीय महानगर बन गया, जिसके आसपास तेंदुओं के साथ-साथ बाघ, ढोल, हाथी, गौर और सांभर जैसे बड़े स्तनधारी जानवरों का पूरा समूह मौजूद है।

(ii) अध्ययन में 34 स्तनपायी प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया गया, जिनमें 4 लुप्तप्राय और 4 निकट संकटग्रस्त प्रजातियां शामिल हैं, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) की लाल सूची द्वारा वर्गीकृत किया गया है।

(iii) इसके अतिरिक्त, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I के अंतर्गत 22 प्रजातियों को तथा अनुसूची II के अंतर्गत 5 प्रजातियों को सूचीबद्ध किया गया।

4. पुडुचेरी नेवा प्लेटफॉर्म अपनाने वाला 19वां विधानमंडल बन गया।



9 जून 2025 को, सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MoI&B) और संसदीय मामलों के मंत्रालय (MPA) के केंद्रीय राज्य मंत्री (MoS) डॉ एल मुरुगन ने पुडुचेरी में पुडुचेरी विधानसभा के लिए राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (NeVA) का उद्घाटन किया।

● उद्घाटन समारोह में पुडुचेरी के उपराज्यपाल के. कैलाशनाथन, मुख्यमंत्री एन. रंगासामी और पुडुचेरी विधानसभा के अध्यक्ष आर. सेल्वम उपस्थित थे।

● डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत मिशन मोड परियोजना नेवा को विधायी प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने, कागज रहित शासन को बढ़ावा देने और नागरिक-केंद्रित विधायी कार्यप्रणाली को बढ़ाने के लिए विकसित किया गया है।

Key Points:-

(i) नेवा "एक राष्ट्र, एक अनुप्रयोग" के दृष्टिकोण के साथ तालमेल बिठाते हुए विधायी कार्यवाही तक वास्तविक समय में पहुँच का समर्थन करता है। यह विधायकों और जनता को डिजिटल माध्यमों के माध्यम से संसदीय गतिविधियों में अधिक कुशलता से शामिल होने की अनुमति देता है।

(ii) इस प्लेटफॉर्म को संसदीय कार्य मंत्रालय (MPA) द्वारा 100% केंद्रीय सहायता से वित्त पोषित किया जाता है।

(iii) यह प्लेटफॉर्म बजट भाषणों, नोटिस और प्रश्नों जैसे विधायी दस्तावेजों तक डिजिटल पहुंच प्रदान करता है, कागज रहित संचालन को सक्षम बनाता है, और BHASHINI (भारत के लिए भाषा इंटरफेस) के माध्यम से AI/ML-संचालित वास्तविक समय अनुवाद को एकीकृत करता है। इसमें पारदर्शिता, सार्वजनिक जुड़ाव और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग भी शामिल है।

5. असम के मुख्यमंत्री ने अनुसंधान विद्वानों का समर्थन करने के लिए 'मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा' योजना का अनावरण किया।



जून 2025 में, असम के मुख्यमंत्री (CM) हिमंत बिस्वा सरमा ने असम के गुवाहाटी में लोक सेवा भवन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री जीवन प्रेरणा योजना की शुरुआत की। यह योजना दिव्यांग (अलग-अलग तरह से सक्षम) विद्वानों पर विशेष जोर देते हुए एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्य भर के शोध विद्वानों को सशक्त बनाने के लिए बनाई गई है, जिसका उद्देश्य असम में अनुसंधान और विकास के एक नए युग को बढ़ावा देना है।

● मुख्यमंत्री जीवन प्रेरणा योजना के तहत पूर्णकालिक शोधार्थियों को 25,000 रुपये, जबकि दिव्यांग शोधार्थियों को एकमुश्त वित्तीय सहायता के रूप में 40,000 रुपये दिए जाएंगे।

● यह योजना असम के स्थायी निवासियों के लिए लागू है जो राज्य और केंद्रीय विश्वविद्यालयों सहित सार्वजनिक संस्थानों में शोध कर रहे हैं।

● इसका उद्देश्य विद्वानों को वित्तीय तनाव के बिना अपने शोध को पूरा करने में सहायता करना है, जिससे शोध उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और शैक्षणिक संस्थानों में उनके रोजगार की संभावनाओं में सुधार होगा।

Key Points:-

(i) मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने स्वागत सतिरथ पोर्टल भी लॉन्च किया, जिसे सरकारी कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने, इसे अधिक कुशल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

(ii) पोर्टल से 9,004 से अधिक ग्रेड III और IV कर्मचारी पहले ही लाभान्वित हो चुके हैं, जो सरकारी सेवाओं में सुविधा बढ़ाने और समग्र उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए पारस्परिक स्थानांतरण की सुविधा प्रदान करता है।

6. सरकार ने वैज्ञानिक उपकरणों की खरीद को सुव्यवस्थित करने के लिए GFR मानदंडों को संशोधित किया।



जून 2025 में, भारत सरकार (GoI) ने रक्षा-संबंधी अनुसंधान में लगे संस्थानों सहित विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानों द्वारा वैज्ञानिक उपकरणों और उपभोग्य सामग्रियों की खरीद के लिए वित्तीय सीमा बढ़ा दी, ताकि देरी को कम किया जा सके और खरीद प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा सके।

● संशोधनों का उद्देश्य प्रशासनिक बाधाओं को कम करके वैज्ञानिक नवाचार और अनुसंधान गतिविधियों में तेजी लाना है।

● वित्त मंत्रालय (MoF) ने खरीद प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और अनुसंधान निकायों की परिचालन स्वायत्तता बढ़ाने के उद्देश्य से सामान्य वित्तीय नियमों (GFRs) के तहत विशेष प्रावधानों में संशोधन किया।

● अनुसंधान एवं विकास (R&D) संस्थानों के कुलपति और निदेशक अब कोटेशन प्राप्त करने की आवश्यकता के बिना 2 लाख रुपये तक के वैज्ञानिक उपकरण और उपभोग्य सामग्रियों (एकल-उपयोग या अल्पकालिक अनुसंधान सामग्री) की खरीद कर सकते हैं।

Key Points:-

(i) संस्थागत क्रय समितियों द्वारा की जाने वाली खरीद के लिए वित्तीय सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है।

(ii) सीमित निविदा जांच (LTE) और विज्ञापित निविदा जांच विधियों के अंतर्गत खरीद सीमा को 50 लाख रुपये से दोगुना करके 1 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

(iii) इन संशोधनों से वैज्ञानिक खरीद में दक्षता बढ़ने तथा भारत में अनुसंधान एवं विकास के लिए अधिक सक्षम वातावरण विकसित होने की उम्मीद है।

INTERNATIONAL

1. सर्वानंद सोनोवाल समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए नॉर्वे और डेनमार्क की 5 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए।



केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) का नेतृत्व करते हुए, 2 जून 2025 से नॉर्वे और डेनमार्क की 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रवाना हुए, जिसका उद्देश्य समुद्री सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है।

- यात्रा के दौरान, उन्होंने नॉर्वे के ओस्लो में नोर-शिपिंग कार्यक्रम के 60वें संस्करण के भाग के रूप में महासागरों पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में भाग लिया, जो एक प्रमुख वैश्विक समुद्री मंच है।

- अपने कार्यक्रमों के भाग के रूप में, मंत्री ने जापान, नॉर्वे और डेनमार्क के अपने समकक्ष मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं, जिनमें बंदरगाह विकास, हरित नौवहन और समुद्री नवाचार में सहयोगात्मक अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

- उन्होंने उन्नत समुद्री प्रौद्योगिकियों को अपनाने, टिकाऊ शिपिंग को बढ़ावा देने और भारत के समुद्री क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के अवसरों का पता लगाने के लिए अग्रणी यूरोपीय शिपिंग कंपनियों, घटक निर्माताओं और प्रौद्योगिकी डेवलपर्स के साथ भी बातचीत की।

Key Points:-

(i) केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल (MoPSW) ने समुद्री संबंधों को मजबूत करने के लिए 2-4 जून, 2025 तक नॉर्वे का दौरा किया। उन्होंने ओस्लो में नॉर-शिपिंग 2025 में भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, जो इसका 60वां संस्करण था। इंडिया @ नॉर-शिपिंग सत्र के दौरान, उन्होंने बुनियादी ढांचे के लिए भारत की 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹1.67 ट्रिलियन) की प्रतिबद्धता की घोषणा की, जिसमें रसद, बंदरगाह संपर्क और व्यापार सुविधा पर ध्यान केंद्रित किया गया।

(ii) इस यात्रा के हिस्से के रूप में, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) ने नॉर्वे स्थित फर्म कॉंग्सबर्ग मैरीटाइम एएस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत भारत के पहले ध्रुवीय अनुसंधान वाहन (PRV) को स्वदेशी रूप से सह-डिजाइन और निर्माण किया जाएगा। PRV का निर्माण GRSE की कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित जहाज निर्माण सुविधाओं में किया जाएगा, जो भारत की ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण कदम है।

(iii) नॉर्वे यात्रा के बाद, मंत्री सोनोवाल द्विपक्षीय समुद्री संबंधों को और मजबूत करने के लिए डेनमार्क गए। उन्होंने डेनमार्क सरकार के उद्योग, व्यापार और वित्तीय मामलों के मंत्री मोर्टेन बोडस्कोव के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों मंत्रियों ने ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप (GSP) और समुद्री मामलों पर मौजूदा समझौता ज्ञापन के तहत सहयोग बढ़ाने पर विचारों का आदान-प्रदान किया, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच टिकाऊ समुद्री प्रथाओं और प्रौद्योगिकी विनिमय को बढ़ावा देना है।

2. ग्लोबल डेटा सेंटर रैंकिंग 2025: मुंबई दुनिया भर में 6वें स्थान पर; वर्जीनिया, USA सूची में शीर्ष पर।



जून 2025 में, इलिनोइस, संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) में मुख्यालय वाली कुशमैन एंड वेकफील्ड इंक (C&W) ने अपनी '2025 वैश्विक डेटा सेंटर बाजार तुलना' रिपोर्ट जारी की।

- रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई (महाराष्ट्र) ने 2024 के अंत तक निर्माणाधीन 335 मेगावाट (MW) डेटा सेंटर क्षमता के साथ 6वीं वैश्विक रैंक हासिल की।
- 1,834 मेगावाट निर्माणाधीन क्षमता के साथ वर्जीनिया (अमेरिका) वैश्विक सूची में शीर्ष पर है, इसके बाद 1,078 मेगावाट के साथ अटलांटा (अमेरिका) और 546 मेगावाट के साथ कोलंबस (अमेरिका) का स्थान है।

Key Points:-

- (i) रिपोर्ट में वर्तमान में निर्माणाधीन डेटा सेंटर क्षमता के आधार पर वैश्विक स्तर पर 97 शहरों को रैंक किया गया।
- (ii) वैश्विक शीर्ष 10 में एकमात्र भारतीय शहर मुंबई, एशिया-प्रशांत (APAC) क्षेत्र में भी अग्रणी है, और APAC में 7वें सबसे स्थापित डेटा सेंटर बाजार के रूप में स्थान दिया गया है।

(iii) पुणे (महाराष्ट्र) और बेंगलुरु (कर्नाटक) को एशिया-प्रशांत के उभरते डेटा सेंटर बाजारों में क्रमशः 4वें और 5वें स्थान पर रखा गया है, जो वैश्विक डिजिटल अवसंरचना परिदृश्य में भारत के बढ़ते महत्व को दर्शाता है।

3. विश्व बैंक ने 3 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन की नई गरीबी रेखा तय की; भारत में अत्यधिक गरीबी घटकर 5.3% हुई।



जून 2025 में, वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) में मुख्यालय वाले विश्व बैंक ने अपना वैश्विक गरीबी अद्यतन जारी किया, जिसमें वैश्विक गरीबी सीमा को संशोधित कर 3 अमेरिकी डॉलर प्रति दिन (3 अमेरिकी डॉलर से कम दैनिक उपभोग) कर दिया गया, जो पहले 2.15 अमेरिकी डॉलर प्रति दिन (2017 की कीमतों के आधार पर) थी।

- रिपोर्ट के अनुसार, भारत की अत्यधिक गरीबी दर 27.1% से घटकर 5.3% हो गई है।
- अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा (IPL) को विश्व बैंक द्वारा 1990 में वैश्विक स्तर पर गरीबी माप को मानकीकृत करने के लिए पेश किया गया था। यह भोजन, कपड़े और आश्रय जैसी बुनियादी आवश्यकताओं के लिए आवश्यक न्यूनतम व्यय को दर्शाता है, और जीवन स्तर की निष्पक्ष अंतर-देशीय तुलना को सक्षम

करने के लिए क्रय शक्ति समता (PPP) का उपयोग करके समायोजित किया जाता है।

Key Points:-

- (i) 2011-12 से 2022-23 तक, भारत में अत्यधिक गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या 344.47 मिलियन से घटकर 75.24 मिलियन हो गई, जो दर्शाता है कि इस अवधि के दौरान लगभग 269 मिलियन लोग गरीबी से बाहर निकले।
- (ii) पांच राज्य- उत्तर प्रदेश (UP), महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल (WB) और मध्य प्रदेश (MP)- जो 2011-12 में भारत के 65% अत्यंत गरीब लोगों के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार थे, 2022-23 तक कुल गरीबी में दो-तिहाई कमी के लिए जिम्मेदार थे।

BANKING & FINANCE

1. SEBI ने सामाजिक, स्थिरता और लिंक्ड बॉन्ड के लिए नए ESG ऋण ढांचे का अनावरण किया।



जून 2025 में, मुंबई, महाराष्ट्र में मुख्यालय वाले पूंजी बाजार नियामक, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) ने भारत में पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) ऋण

प्रतिभूतियों के जारी करने और सूचीबद्ध करने के लिए एक नया नियामक ढांचा पेश किया।

- यह व्यापक ढांचा विशेष रूप से सामाजिक बॉन्ड, स्थिरता बॉन्ड और स्थिरता-लिंक्ड बॉन्ड (SLBs) पर लागू होता है, जबकि ग्रीन बॉन्ड को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। ये नए नियम आधिकारिक तौर पर 5 जून, 2025 को लागू हुए।
- इस पहल का उद्देश्य पारदर्शिता, विश्वसनीयता और निवेशक विश्वास को बढ़ाकर भारत के ESG ऋण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है, जिससे देश के व्यापक सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) का समर्थन किया जा सके और जिम्मेदार वित्तपोषण को बढ़ावा दिया जा सके।
- जून 2025 में, SEBI ने अपने 2025-2028 सस्टेनेबल फाइनेंस रोडमैप के तहत एक नया ESG ऋण ढांचा शुरू किया। इसमें ग्रीन बॉन्ड को छोड़कर सामाजिक, स्थिरता और स्थिरता-लिंक्ड बॉन्ड (SLBs) शामिल हैं। यह ढांचा ICMA सिद्धांतों और आसियान दिशानिर्देशों जैसे वैश्विक मानकों के अनुरूप है, जिसके तहत आवश्यक सेवाओं, बुनियादी ढांचे, रोजगार और खाद्य सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए सामाजिक बॉन्ड की आवश्यकता होती है।

Key Points:-

- (i) इस ढांचे में जारी करने से पहले और बाद में विस्तृत खुलासे अनिवार्य हैं। जारीकर्ताओं को उद्देश्य, परियोजना चयन और लक्षित लाभार्थियों को पहले ही साझा करना चाहिए। जारी करने के बाद, वार्षिक रिपोर्ट में फंड के उपयोग, अप्रयुक्त आय और प्रभाव मीट्रिक को रेखांकित करना चाहिए। यह पारदर्शिता सुनिश्चित करता है और

हितधारकों को ESG परियोजनाओं के सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करने की अनुमति देता है, जिससे ESG ऋण बाजार में जवाबदेही मजबूत होती है।

(ii) SEBI के ढांचे में सभी ESG-लेबल वाले बॉन्ड के लिए स्वतंत्र तृतीय-पक्ष सत्यापन अनिवार्य है। बॉन्ड को सामाजिक, स्थिरता या SLB के रूप में योग्य बनाने के लिए, आय को ESG लक्ष्यों के साथ संरेखित परियोजनाओं को निधि देना चाहिए। SLB जारीकर्ताओं को स्थिरता रणनीतियों, प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (KPI) और स्थिरता प्रदर्शन लक्ष्यों (SPT) का खुलासा करना चाहिए। तृतीय-पक्ष समीक्षक यह आकलन करते हैं कि क्या ये लक्ष्य विश्वसनीय और प्राप्त करने योग्य हैं, यह सुनिश्चित करके निवेशकों का विश्वास मजबूत करते हैं कि बॉन्ड वास्तव में सतत विकास उद्देश्यों का समर्थन करते हैं।

(iii) रूपरेखा तीन ESG ऋण प्रकारों को परिभाषित करती है: सामाजिक बॉन्ड आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसी परियोजनाओं को निधि देते हैं; स्थिरता बॉन्ड पर्यावरण और सामाजिक दोनों लक्ष्यों का समर्थन करते हैं; SLBs निर्धारित स्थिरता लक्ष्यों (SPTs) को पूरा करने वाले जारीकर्ताओं से जुड़े होते हैं, जिनके परिणामों के आधार पर पुरस्कार या दंड दिए जाते हैं। ये श्रेणियां भारत के पूंजी बाजारों को वैश्विक स्थिरता मानदंडों के अनुरूप बनाती हैं।



9 जून 2025 को, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत डिजिटल इंडिया भाषिणी (भारत के लिए भाषा इंटरफेस) प्रभाग (DIBD) ने भारतीय रेलवे के प्रमुख सार्वजनिक-सामने वाले प्लेटफार्मों पर बहुभाषी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) समाधानों को सहयोगात्मक रूप से विकसित और तैनात करने के लिए नई दिल्ली, दिल्ली में मुख्यालय वाले रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र (CRIS) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।

- भाषिणी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) अमिताभ नाग और क्रिस के प्रबंध निदेशक (MD) जी.वी.एल. सत्य कुमार ने नई दिल्ली में आधिकारिक तौर पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

- सहयोग का उद्देश्य यात्रियों को 22 भारतीय भाषाओं में आवश्यक रेलवे सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना है, जिससे भाषा संबंधी बाधाएं दूर होंगी और सार्वजनिक सेवा वितरण की समावेशिता में सुधार होगा।

Key Points:-

(i) समझौता ज्ञापन में BHASHINI की उन्नत भाषा AI प्रौद्योगिकियों को राष्ट्रीय रेल पूछताछ प्रणाली (NTES) और रेलमदद एप्लिकेशन सहित प्रमुख भारतीय रेलवे डिजिटल

MOUs and Agreement

1. भारतीय रेलवे के लिए बहुभाषी AI उपकरण विकसित करने के लिए BHASHINI और CRIS ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

प्लेटफार्मों में एकीकृत करके भाषाई समावेशिता और पहुंच को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

(ii) एकीकरण में BHASHINI की भाषा प्रौद्योगिकी स्टैक शामिल होगी, जिसमें स्वचालित भाषण पहचान (ASR), टेक्स्ट-टू-टेक्स्ट (TTT) अनुवाद, टेक्स्ट-टू-स्पीच (TTS), और ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन (OCR) शामिल हैं, जो CRIS-प्रबंधित रेलवे सिस्टम में शामिल हैं।

(iii) साझेदारी का उद्देश्य बहुभाषी चैटबॉट, वॉयस असिस्टेंट और ओवर-द-काउंटर पूछताछ इंटरफेस का सह-विकास करना भी है, जो भारतीय रेलवे (IR) में विविध भाषाई दर्शकों के लिए उपयोगकर्ता अनुभव को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है।

2024 में बिबेक देबरॉय के निधन के बाद कार्यभार संभाला था।

- अपनी नियुक्ति के बाद, प्रोफेसर महेंद्र देव ने एक्सिस बैंक के निदेशक मंडल से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि अध्यक्ष की भूमिका एक पूर्णकालिक पद है।

- EAC-PM के पुनर्गठन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंजूरी दी और कैबिनेट सचिवालय ने इसे अधिसूचित किया। नए अंशकालिक सदस्यों में सौम्य कांति घोष, के वी राजू, चेतन घाटे, पमी दुआ, पुलक घोष और गौरव वल्लभ शामिल हैं, जबकि पूनम गुप्ता को बाहर रखा गया है।

Key Points:-

(i) प्रोफेसर देव ने 1988 में इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान (IGIDR) से अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू की और 2010 से 2022 तक इसके निदेशक और कुलपति के रूप में कार्य किया।

(ii) प्रोफेसर देव कोटक महिंद्रा बैंक (2013-2021) और एक्सिस बैंक (2021-2025) में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य कर चुके हैं। वे वर्तमान में इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, आंध्र प्रदेश (अंशकालिक) के अध्यक्ष हैं और अगस्त 2023 से इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के संपादक हैं।

(iii) प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) एक गैर-संवैधानिक, गैर-सांविधिक, स्वतंत्र सलाहकार निकाय है जो सीधे भारत के प्रधानमंत्री को आर्थिक अंतर्दृष्टि और सिफारिशें प्रदान करता है। इसमें एक अध्यक्ष के साथ-साथ पूर्णकालिक और अंशकालिक सदस्य शामिल होते हैं।

APPOINTMENTS & RESIGNATIONS

1. एस महेंद्र देव को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया।



जून 2025 में, भारत सरकार ने प्रख्यात अर्थशास्त्री प्रोफेसर एस महेंद्र देव को दो साल के कार्यकाल के लिए प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) का अध्यक्ष नियुक्त किया, जो सुमन बेरी का स्थान लेंगे, जिन्होंने नवंबर

SPORTS

1. भारत ने 2025 ताइवान एथलेटिक्स ओपन में चमक बिखेरी, 12 स्वर्ण सहित 16 पदक जीते।



विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर ब्रॉन्ज़ (श्रेणी C) का एक हिस्सा, 2025 ताइवान एथलेटिक्स ओपन, 7 जून से 8 जून, 2025 तक ताइपे म्यूनिसिपल स्टेडियम, ताइपेई शहर, ताइवान में आयोजित किया गया था।

- भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 16 पदक जीते, जिनमें 12 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य शामिल थे।
- भारत ने मजबूत दावेदार ऑस्ट्रेलिया और जापान को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने अंतिम पदक तालिका में क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया।
- 2024 ताइवान एथलेटिक्स ओपन में, भारत ने 3 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते थे, जो 2025 में उल्लेखनीय सुधार दर्शाता है।

Key Points:-

- (i) 34 सदस्यीय भारतीय दल ने विभिन्न ट्रैक और फील्ड स्पर्धाओं में असाधारण प्रदर्शन किया।
- (ii) अन्नू रानी (भाला फेंक), रोहित यादव (भाला फेंक),

ज्योति वरराजी और पूजा (800 मीटर) जैसे उल्लेखनीय एथलीट शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में शामिल थे, जिनमें से कई ने रिकॉर्ड तोड़ उपलब्धियां हासिल कीं।

2. इंडोनेशिया ओपन 2025: एंडर्स एंटोनसेन ने पुरुष एकल का खिताब जीता और एन से-यंग ने महिला एकल में जीत हासिल की।



8 जून, 2025 को, डेनमार्क के विश्व नंबर 3 शटलर एंडर्स एंटोनसेन ने इंडोनेशिया के जकार्ता के गेलोरा बुंग कानो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित फाइनल मैच में ताइवान के चोउ तिएन-चेन को हराकर अपना पहला इंडोनेशिया ओपन पुरुष एकल खिताब हासिल किया।

● महिला एकल वर्ग में, विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी दक्षिण कोरिया की एन से-यंग ने विश्व की नंबर 2 खिलाड़ी चीन की वांग झियी को हराकर अपना दूसरा इंडोनेशिया ओपन खिताब जीता।

Key Points:-

- (i) इंडोनेशिया ओपन का 43वां संस्करण, जिसे आधिकारिक तौर पर कपाल एपी इंडोनेशिया ओपन 2025 के नाम से

जाना जाता है, 3 से 8 जून, 2025 तक इस्टोरा गेलोरा बुंग कार्ना, जकार्ता, इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। यह एक प्रमुख बैडमिंटन टूर्नामेंट था, जिसमें कुल पुरस्कार राशि 1,450,000 अमेरिकी डॉलर थी।

(ii) इंडोनेशिया बैडमिंटन एसोसिएशन (PBSI) द्वारा 1982 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाने वाला यह आयोजन BWF वर्ल्ड टूर का हिस्सा है और इसमें शीर्ष वैश्विक खिलाड़ी भाग लेते हैं।

SUMMITS & CONFERENCE / COMMITTEES & MEETINGS

1. पुर्तगाल ने स्पेन के खिलाफ पेनल्टी शूटआउट जीत के बाद दूसरा UEFA नेशंस लीग खिताब जीता।



जून 2025 में पुर्तगाल ने फाइनल में 2-2 से ड्रों के बाद स्पेन को पेनल्टी पर 5-3 से हराकर अपना दूसरा यूईएफए नेशंस लीग खिताब हासिल किया। यह मैच एलियांज एरिना, म्यूनिख, जर्मनी में आयोजित किया गया था, जिसके साथ टूर्नामेंट का चौथा संस्करण समाप्त हो गया, जो सितंबर 2024 से जून 2025 तक चला।

- स्पेन ने मार्टिन जुबिमेंडी (21वें मिनट) और मिकेल ओयारजाबल (45वें मिनट) के गोल से बढ़त हासिल की। पुर्तगाल ने नूनो मेंडेस (26वें मिनट) और क्रिस्टियानो रोनाल्डो (61वें मिनट) के गोल से बराबरी की, जिससे मैच अतिरिक्त समय और अंततः पेनल्टी में चला गया, जहाँ पुर्तगाल ने जीत हासिल की।

- क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपना 138वां अंतरराष्ट्रीय गोल किया, जिससे वह UEFA नेशंस लीग फाइनल में गोल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी (40 वर्ष से अधिक) बन गए, उन्होंने लुका मोड्रिक को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 2023 के फाइनल में 37 वर्ष की उम्र में पिछला रिकॉर्ड बनाया था।

- इस जीत के साथ, पुर्तगाल UEFA नेशंस लीग का खिताब दो बार जीतने वाला पहला देश बन गया - पहली बार 2019 में (नीदरलैंड के खिलाफ) और अब 2025 में (स्पेन के खिलाफ)।

Key Points:-

(i) नूनो मेंडेस को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, उन्होंने फाइनल में महत्वपूर्ण गोल किया तथा सेमीफाइनल मैच में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया।

(ii) हार के बावजूद, स्पेन ने 2024-25 UEFA नेशंस लीग के दौरान 25 गोल करके एक रिकॉर्ड बनाया - जो टूर्नामेंट के एक संस्करण में किसी भी टीम द्वारा बनाए गए सबसे अधिक गोल हैं।

(iii) पुर्तगाल (ग्रुप एफ) और स्पेन (ग्रुप ई) दोनों अब अपना ध्यान फीफा विश्व कप 2026 यूरोपीय क्वालीफायर पर लगाएंगे, जो सितंबर 2025 में फिर से शुरू होने वाला है।

IMPORTANT DAYS

1. संयुक्त राष्ट्र 10 जून 2025 को सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया।



सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए पहला संयुक्त राष्ट्र (UN) अंतर्राष्ट्रीय दिवस 10 जून 2025 को विश्व स्तर पर मनाया गया। इस दिवस का उद्देश्य बढ़ते विभाजन और संकटों का सामना कर रहे विश्व में अंतर-सांस्कृतिक समझ, आपसी सम्मान और वैश्विक एकजुटता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।

- यह दिवस शांति, विकास, विश्वास, प्रभावी शासन और सार्वभौमिक मानवाधिकारों के संरक्षण को बढ़ावा देने में संवाद की आवश्यक भूमिका को रेखांकित करता है।

- 7 जून 2024 को, संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने अपनी 88वीं पूर्ण बैठक के दौरान संकल्प A/RES/78/286 को अपनाया, जिसके तहत प्रत्येक वर्ष 10 जून को सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया।

- यह प्रस्ताव चीन द्वारा प्रस्तावित किया गया था और इसे 80 से अधिक देशों से सह-प्रायोजन प्राप्त हुआ, जो अंतर-

सांस्कृतिक संवाद के लिए व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन को दर्शाता है।

Key Points:-

(i) इस दिवस को मनाने के लिए, UNESCO ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के UNESCO में स्थायी प्रतिनिधिमंडल के साथ मिलकर 5 जून 2025 को "सिल्क रोड के साथ भविष्य पर युवा संवाद" शीर्षक से एक विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया।

(ii) यह कार्यक्रम पेरिस, फ्रांस में UNESCO मुख्यालय में आयोजित किया गया, जिसमें अंतर-सांस्कृतिक सहयोग और समझ के भविष्य के मार्ग को आकार देने में युवाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला गया।

2. रेलवे सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय लेवल क्रॉसिंग जागरूकता दिवस मनाया गया।



अंतर्राष्ट्रीय लेवल क्रॉसिंग जागरूकता दिवस (ILCAD) 2025 को 5 जून को विश्व स्तर पर लेवल क्रॉसिंग से उत्पन्न खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया गया - जहाँ रेलवे लाइनें सड़कों से मिलती हैं - और सड़क उपयोगकर्ताओं और

पैदल चलने वालों के बीच सुरक्षित व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए।

- ये चौराहे टकराव के लिए उच्च जोखिम वाले क्षेत्र हैं, जिससे शिक्षा और सतर्कता आवश्यक हो जाती है।
- ILCAD का 17वाँ संस्करण 5 जून 2025 को मनाया गया, जो कि 4 जून 2025 को मनाए जाने वाले अतिचार रोकथाम जागरूकता दिवस (TRESPAD) के बाद मनाया गया।
- TRESPAD का ध्यान रेल से संबंधित अतिचार की घटनाओं को कम करने पर है, जो दुनिया भर में रेलवे दुर्घटनाओं में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

Key Points:-

- ILCAD का समन्वय अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ (UIC) (फ्रेंच में यूनियन इंटरनेशनल डेस केमिन्स डे फेर) द्वारा किया जाता है और इसे दुनिया भर के रेलवे संगठनों द्वारा सक्रिय रूप से समर्थन दिया जाता है।
- 2025 में, ILCAD और TRESPAD के लिए लॉन्च कॉन्फ्रेंस की मेजबानी यूनाइटेड किंगडम (UK) स्थित नेटवर्क रेल और रेल सुरक्षा और मानक बोर्ड (RSSB) द्वारा यॉर्क, यूके में राष्ट्रीय रेलवे संग्रहालय में की गई थी।
- ILCAD 2025 का विषय "लोगों को अच्छे निर्णय लेने में मदद करना" है, जिसका नारा है: "हर बार सुरक्षित निर्णय", जिसका उद्देश्य दुर्घटनाओं को रोकने और जीवन बचाने के लिए लेवल क्रॉसिंग पर विचारशील और जिम्मेदार व्यवहार को प्रोत्साहित करना है।

SCIENCE AND TECHNOLOGY

1. ध्रुव स्पेस ने होरस स्टार ट्रैकर मिशन के लिए फ्रांस के सोडर्न एरियन ग्रुप के साथ सहयोग किया।



जून 2025 में, हैदराबाद (तेलंगाना) स्थित ध्रुव स्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने एरियनग्रुप की सहायक कंपनी लाइमिल-ब्रेवनेस (फ्रांस) स्थित सोडर्न के साथ रणनीतिक सहयोग की घोषणा की, ताकि 2026 में लॉन्च होने वाले ध्रुव स्पेस-होस्टेड पेलोड मिशन पर सोडर्न के उच्च सटीकता वाले होरस स्टार ट्रैकर को तैनात किया जा सके।

- यह मिशन 'एस्पारिंग पेलोड्स के लिए प्रक्षेपण अभियान' (LEAP) पहल का हिस्सा होगा।
- इस साझेदारी की आधिकारिक घोषणा केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में यूरोप में भारत विनिर्माण (HCIM) व्यापार प्रतिनिधिमंडल की उच्च स्तरीय समिति की बैठक के दौरान की गई।
- होरस स्टार ट्रैकर को ध्रुव स्पेस के स्वदेशी रूप से निर्मित P-30 नैनोसैटेलाइट प्लेटफॉर्म में एकीकृत किया जाएगा। मॉड्यूलर आर्किटेक्चर पर आधारित इस प्लेटफॉर्म को पहले जनवरी 2024 में ISRO के PSLV-C58 POEM-3 (PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरीमेंटल मॉड्यूल-3) मिशन के दौरान अंतरिक्ष-योग्य

घोषित किया गया था, जिससे भविष्य के सैटेलाइट मिशनों के लिए इसकी क्षमताओं की पुष्टि हुई।

Key Points:-

- (i) सोडरन के HORUS पेलोड में अत्याधुनिक सक्रिय पिक्सेल सेंसर (APS) स्पेस डिटेक्टर है, जिसे दूरसंचार प्लेटफार्मों में उच्च परिशुद्धता, स्वायत्त दृष्टिकोण संवेदन के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- (ii) यह प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष यान अभिविन्यास सटीकता को बढ़ाती है, जिससे निम्न-पृथ्वी कक्षा (LEO) संचालन में मिशन के प्रदर्शन में सुधार होता है।
- (iii) इसके अतिरिक्त, कैलिफोर्निया (USA) में विकसित सोडरन के विकिरण-कठोर ऑरिगा स्टार ट्रैकर को ध्रुव स्पेस द्वारा अपने आगामी उपग्रह मिशनों की एक श्रृंखला के लिए पसंदीदा एटीट्यूड डिटरमिनेशन एंड कंट्रोल सिस्टम (ADCS) के रूप में चुना गया है, जिससे भारत-फ्रांस एयरोस्पेस सहयोग मजबूत होगा।

ENVIRONMENT

1. वैज्ञानिकों ने चंडीगढ़ में नई ततैया प्रजाति 'लोसग्ना ऑक्सिडेंटलिस' की खोज की।



जून 2025 में, पशु वर्गीकरण के लिए सहकर्म-समीक्षित वैज्ञानिक पत्रिका जूटाक्सा में प्रकाशित एक अध्ययन में, लगभग 60 वर्षों के बाद भारत में ततैयों की लॉसग्ना प्रजाति की पुनः खोज की सूचना दी गई थी।

- चंडीगढ़ में खोजी गई नई प्रजाति को लॉसग्ना ऑक्सिडेंटलिस नाम दिया गया है, जो इस वंश की सबसे पश्चिमी उपस्थिति को चिह्नित करता है, जो पहले केवल पूर्वीभारत के उष्णकटिबंधीय जंगलों और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में पाया जाता था।

Key Points:-

- (i) हिमालयी जैव विविधता के लिए एक संबंधित मील के पत्थर के रूप में, उत्तराखंड के उच्च ऊंचाई वाले जंगलों में, विशेष रूप से केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य के भीतर, मायोटिस हिमालयकस (हिमालयी लंबी पूंछ वाले मायोटिस) नामक एक नई चमगादड़ प्रजाति की खोज की गई।
- (ii) यह खोज, जिसे जूटाक्सा में भी प्रकाशित किया गया था, का नेतृत्व पांच सदस्यीय टीम ने किया था जिसमें भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI) के उत्तम सैकिया और नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन के रोहित चक्रवर्ती शामिल थे। यह पश्चिमी हिमालय में चमगादड़ जीवों के व्यापक पुनर्मूल्यांकन का हिस्सा था।
- (iii) ये खोजें पारिस्थितिक समृद्धि और विविध भारतीय आवासों में निरंतर जैव विविधता अनुसंधान के महत्व को रेखांकित करती हैं।

Static GK

| | | |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Denmark | राजधानी: कोपेनहेगन | प्रधान मंत्री: मेटे फ्रेडरिकसन |
| Securities and Exchange Board of India (SEBI) | अध्यक्ष: तुहिन कांता पांडे | मुख्यालय: मुंबई |
| Dhruva Space | स्थापना: 2012 | मुख्यालय: हैदराबाद |
| Athletics Federation of India (AFI) | अध्यक्ष: बहादुर सिंह सागू | मुख्यालय: नई दिल्ली |
| Union of European Football Associations (UEFA) | राष्ट्रपति: अलेक्जेंडर सेफ़रिन | मुख्यालय: न्योन, स्विटजरलैंड |
| International Union of Railways (UIC) | महानिदेशक (DG): फ़्राँस्वा डेवेन | मुख्यालय: पेरिस, फ़्रांस |
| Assam | मुख्यमंत्री (CM) : हिमंत बिस्वा सरमा | राज्यपाल : लक्ष्मण आचार्य |
| World Bank | अध्यक्ष: अजय बंगा | मुख्यालय: वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) |
| Badminton World Federation (BWF) | राष्ट्रपति: खुनयिंग पटामा लीस्वाडन्नकुल | मुख्यालय: कुआलालंपुर, मलेशिया |